गया है कि जो एरियर्स वगैरह हैं, वे दें। लांग टर्म बेसिस पर सरकार ने जो नीति बनाई है, उससे हम यह समझते हैं कि सुगर मिलों की वायबिलिटी बढ़ेगी। कुछ हम यह चाहते हैं कि खासतौर पर यू०पी० और बिहार में और दूसरी जगह सुगर मिल का डायरेक्ट लिंक सुगरकेन ग्रोअर से (व्यवधान) हो...

WELCOME TO THE POLISH PARLIAMENTARY DELEGATION

Welcome to the polish parliamentary delegation

MR. CHAIRMAN: Hon'ble Members, I have an announcement to make.

We have with us this morning, seated in the Special Box, Members of the Polish Parliamentary Delegation which is currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Mr. Roman Malinowski, Speaker of Parliament of the Polish People's Republic. The other Members of the Delegation are:

1. Mr. Marek Wieczorek
2. Mr. Zdzislaw Balicki
3. Mr. Bogdan Krolewski
4. Mrs. Jozefa A. Matynkowska
5. Mrs. Irena Szczygielska
6. Mr. Jozef Kielb

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a very hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and wish our distinguished guests a very enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn about our country, our parliamentary system and our people. Through them we convey our greetings and best wishes to the Members of Parliament of the Polish People's Republic and the friendly people of Poland.

Now Shri Satya Pal Malik.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो मिलों के बन्द होने की स्थिति के बारे में बताया, वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसान नाराज थे, मिलें बन्द हो सकती थीं, लेकिन हुई नहीं, इसलिये कि जो मिलें बन्द करवाना चाहते थे, वे तो गन्ना दो रुपये मन बिकवाना चाहते थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रायवेट मिलों के मालिक हैं, वे गन्ने के मौजूदा दाम से ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ इस तरह के प्रशासनिक दबाव डाले जा रहे हैं कि वे अधिक दाम न दें जिससे किसानों में व्यापक असंतोष है। क्या इस बात की जानकारी करके वे सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इसकी जानकारी करूंगा। हम त चाहते हैं कि जितना अधिक किसानों क दिया जा सके, दिया जाना चाहिये। जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसकी जानकारी मैं जरूर करूंगा।

श्री सूरज प्रसाद : मान्यवर, सुगरकेन का प्रोडक्शन पिछले दो तीन सालों से घट रहा है और उसका प्रधान कारण यह है कि सरकार किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस सुगरकेन का नहीं देती है और दूसरा कारण यह है कि किसानों का मिलों के पास बकाया रहता है, खासकर यू०पी० और बिहार में। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सुगरकेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये इस बात पर ध्यान देगी कि किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाये क्योंकि शुगरकेन कमिश्नर को तो 28 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है और गवर्नमेंट 18 रुपये प्रति क्विंटल देती है ?